EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Aarav Anand

Date: 05-12-2025

Source- जनसत्ता

आर्थिक रणनीति का खाका तैयार करने को

मोदी और पुतिन की बैठक आज

लाल कालीन पर अगवानी करने खुद पहुंचे प्रधानमंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

आर्थिक रणनीति का खाका तैयार करने को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को शाम को दो दिन के दौरे पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम हवाई अड्डे पर गले लगाकर पुतिन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे दोस्त पुतिन का स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं। चार साल के अंतराल के बाद यात्रा पर आए राष्ट्रपति पुतिन करीब 27 घंटे भारत में बिताएंगे।

दोनों नेता एक ही कार में हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए निकले।

करीब तीन महीने पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के बाद चीन के शहर तियानजिन में उन्होंने एक ही वाहन में साथ यात्रा की थी। रूस व यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बाद पुतिन की यह पहली भारत यात्रा है। भारत इस दौरे को कितनी अहमियत दे रहा है, यह इस बात से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार शाम को पुतिन के लिए एक निजी रात्रिभोज का आयोजन किया।

पिछले साल जुलाई में रूस की राजधानी मास्को के दौरे के दौरान रूसी नेता ने भी भारत के प्रधानमंत्री की मेहमान नवाजी की थी। इस बैठक पर पश्चिमी देशों की करीबी नजर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं।

भारत और रूस की दोस्ती मुश्किल समय में कसौटी पर खरी उतरी है। पुतिन शुक्रवार को होने वाली 23वीं भारत-रूस शिखर वार्ता में भाग लेंगे, जिसके कई महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलने की संभावना है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली वार्ता का मुख्य विषय रक्षा संबंधों को मजबूत करना, भारत-रूस व्यापार को बाहरी दबाव से सुरक्षित रखना और छोटे माड्यूलर संयंत्रों में सहयोग की संभावनाओं की तलाश जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगा।

पुतिन का यह भारत दौरा करीब आठ दशक पुरानी भारत-रूस साझेदारी को और मजबूत करना है, एक ऐसी साझेदारी जो जटिल भू-राजनीतिक **बाकी पेज 8 पर**

यूक्रेन से युद्ध के बाद पहली बार भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति आज सुबह राजघाट जाएंगे, रूसी सरकारी प्रसारक का नया 'इंडिया चैनल' शुरू करेंगे।

नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

'यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा भारत'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी इस साल भारत करने जा रहा है। जिसकी तैयारियां तेजी से लालकिला में चल रही है और उसे सजाया जा रहा है। बता दें कि यह आयोजन 8–13 दिसंबर तक चलेगा। इसका लक्ष्य है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत नामांकनों की जांच, मौजूदा तत्वों की स्थिति की समीक्षा व ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता प्रदान करना।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर का इस बारे में जवाब देते हुए कहा कि भारत के वर्तमान में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में 15 तत्व शामिल हैं। इस बैठक के दौरान संभावित मुख्य मुद्दे उठाए जाएंगे, जिनमें मौजूदा सूचीबद्ध तत्वों के बारे में राज्यों द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा रपटों का मूल्यांकन, ऐसी विरासतों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता का अनुरोध, 'जीवित विरासत सुरक्षा', सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन सुरक्षा पद्धतियों पर चर्चा और भविष्य की योजना। इस आयोजन में समिति के सदस्यों, यूनेस्को के अधिकारियों, विशेषज्ञों, मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों और पेशेवरों सहित 180 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।

घरेलू खपत और अर्थव्यवस्था की राह

अमेरिका की ओर से भारत पर पचास फीसद तक शुल्क लगाए जाने के बाद भारत ने रूस और चीन के साथ आर्थिक-वैश्विक कूटनीति और नए निर्यात बाजारों के साथ घरेलू खपत के मोर्चे पर आगे बढ़ने की जो रणनीति अपनाई, वह कारगर दिखाई दे रही है।

जयंतीलाल भंडारी

भारत की घरेलू खपत विकास दर को आगे बढ़ाते हुए देश की आर्थिक ताकत बन गई है। हाल ही में सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2025-26 में जुलाई-सितंबर की तिमाही में 8.2 फीसद बढ़ी है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 5.6 फीसद थी। खास बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास दर के मामले में दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। यह संभावना दिखाई दे रही है कि इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान से अधिक 7.5 फीसद के स्तर पर दिखाई देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 8.2 फीसद की विकास दर वृद्धि समर्थक नीतियों और सुधारों के प्रभाव को बताती है, वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारोबारी सुगमता और उत्पादकता बढ़ाने जैसे कदमों से जीडीपी बढ़ी है।

इन दिनों भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित हो रही विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय संगठनों की रपटों में कहा जा रहा है कि भारत में महंगाई घटने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर में कटौती से उपभोग और घरेलू खपत में जोरदार इजाफा होने से विकास दर बढ़ी है। जहां भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिकी शुल्क का प्रतिकूल असर झेल गई, वहीं निर्यात, पूंजीगत निवेश और निवेश रुझान पर प्रतिकूल असर की चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ी है। साथ ही यह वैश्विक अनिश्चितताओं से पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने की स्थिति में है।

गौरतलब है कि इस बार दिवाली पर बाजार में बिक्री रेकार्ड ऊंचाई पर रही है। ई-वाणिज्य ने दमदार उछाल दर्ज की है। महंगाई के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी के कारण जीएसटी बचत उत्सव का परिदृश्य दिखाई दिया है। जब दुनिया के अधिकांश देशों में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, वहीं भारत में महंगाई में कमी के आंकड़े सामने आए। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी रपट में कहा गया है कि जहां अक्तूबर 2025 में खुदरा महंगाई घट कर पिछले दस वर्ष के न्यूनतम स्तर 0.25 फीसद पर आ गई, वहीं थोक महंगाई 27 महीने के निचले स्तर शून्य से 1.21 फीसद नीचे रही है। महंगाई में यह कमी प्रमुख रूप से सब्जियां, फल, अंडे, अनाज एवं उससे बने उत्पाद, बिजली, परिवहन और संचार आदि मदों की महंगाई में गिरावट के कारण आई है। महंगाई कम होने के पीछे इस वर्ष 22 सितंबर से लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार की भी अहम भूमिका है। जीएसटी दरों में की गई कमी से खाने-पीने की सभी वस्तुएं सस्ती हुई हैं। क्रिसिल की एक रपट के अनुसार अक्तूबर 2025 में शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 17 फीसद सस्ती होकर 27.8 रुपए और मांसाहारी थाली 12 फीसद सस्ती होकर 54.4 रुपए के मूल्य स्तर पर पाई गई। यह बात भी अहम है कि इस समय विभिन्न शोध रपटों में यह भी कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के रेकार्ड उत्पादन और अच्छे मानसून के बाद कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को मिली अनुकूलता से आगामी महीनों में भी महंगाई में और कमी आने की उम्मीद

है। अनुमान है कि इस वित्त वर्ष 2025-26 में औसतन खुदरा महंगाई दर 2.5 फीसद रह सकती है, जो पिछले वर्ष के 4.6 फीसद के मुकाबले काफी कम होगी। हालांकि जमीनी स्तर पर महंगाई में कमी को लेकर हकीकत अलग देखने में आती है, लेकिन औपचारिक रूप से सार्वजनिक किए गए आंकड़े ही आकलन का आधार बनते हैं।

> **महंगाई दर घटने के साथ-साथ जीएसटी सुधारों के लागू होने से इस बार दिवाली पर बाजार में खरीदी को पंख लगते दिखाई दिए। जीएसटी में सरलता और कर ढांचों में बदलाव ने बाजार को नई ऊर्जा दी। जीएसटी दरों के साथ-साथ आयकर में कटौती से लोगों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। फेडरेशन आफ इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक जहां वर्ष 2023 में त्योहारी बाजार में 3.75 लाख करोड़ रुपए और वर्ष 2024 में 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी, वहीं इस बार त्योहारी मौसम के तहत खरीदारी पांच लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई।**

यह बात अहम है कि महंगाई दर घटने के साथ-साथ जीएसटी सुधारों के लागू होने से इस बार दिवाली पर बाजार में अच्छी खरीदारी दिखाई दी। जीएसटी में सरलता और कर ढांचों में बदलाव ने बाजार को नई ऊर्जा दी। जीएसटी दरों के साथ-साथ आयकर में कटौती से लोगों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। फेडरेशन आफ इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के मुताबिक जहां वर्ष 2023 में त्योहारी बाजार में 3.75 लाख करोड़ रुपए और वर्ष 2024 में 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी, वहीं इस बार त्योहारी सीजन के तहत खरीदारी पांच लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। इस बार दिवाली पर देश में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने और अमेरिका में डालर का मूल्य घटने से इस साल त्योहारी सीजन में चांदी और सोने के भाव भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहे। वहीं इस समय औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है और विनिर्माण क्षेत्र से लेकर सेवा क्षेत्र तक मांग का बढ़ता हुआ नया अध्याय दिखाई दे रहा है। मांग और उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है।

भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के पीछे जीएसटी सुधार के साथ-साथ कुछ और आर्थिक अनुकूलताएं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर पचास फीसद शुल्क लगाए जाने के बाद भारत ने रूस और चीन के साथ आर्थिक-वैश्विक कूटनीति और नए निर्यात बाजारों में आगे बढ़ने की जो रणनीति अपनाई, वह कारगर दिखाई दे रही है। इस नीति से अमेरिकी शुल्क के बीच पिछले अगस्त से अक्तूबर में अमेरिका को छोड़ कर अन्य देशों में भारत के निर्यात बढ़े हैं। इसी के साथ विभिन्न देशों के साथ तेजी से आकार लेते हुए दिखाई दे रहे मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भारतीय निर्यात के लिए मील का पत्थर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं नए श्रम कानून भी देश के आर्थिक विकास में नई प्रभावी भूमिका निभाएंगे।

हाल ही में 'एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स' ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5 फीसद और अगले वित्त वर्ष 2026-27 में 6.7 फीसद की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। 'एसएंडपी' ने कहा है कि जीएसटी की कम दरें मध्य वर्ग के उपभोग को बढ़ावा देंगी और इस वर्ष शुरू की गई आयकर कटौती एवं ब्याज दरों में कटौती का पूरक बनेंगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नई रपट में कहा है कि हालांकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और व्यापार तनाव के बीच वैश्विक वृद्धि दर धीमी है। इसके बावजूद भारत मजबूत घरेलू खपत के दम पर 6.6 फीसद विकास दर हासिल करते हुए दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक विकास दर की संभावनाएं रखता है।

जीएसटी के बाद अब ऊंची आर्थिक विकास दर के मद्देनजर अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। इन सुधारों में जीवन में आसानी, कारोबार सुगमता, बुनियादी ढांचा सुधार, प्रशासन को सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने संबंधी सुधार शामिल हैं। साथ ही देश को कृषि, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज आदि में सुधारों की डगर पर आगे बढ़ना होगा। ऐसे में बढ़ती हुई घरेलू खपत और नई पीढ़ी के सुधार देश को वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक दुनिया का विकसित देश बनाने की डगर पर आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा

भारत-रूस व्यापार को अधिक संतुलित बनाने की जरूरत

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (भाषा)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने तथा इसे और अधिक संतुलित बनाने की दिशा में काम करने के व्यापक अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता वस्तुएं, खाद्य उत्पाद, मोटर वाहन, ट्रैक्टर, भारी वाणिज्यिक वाहन, स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रानिक, औद्योगिक कल-पुर्जे और वस्त्र भारत से रूस को निर्यात बढ़ाने की क्षमता रखने वाले में क्षेत्रों में शामिल हैं।

गोयल ने उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित भारत-रूस व्यापार मंच की बैठक में कहा द्विपक्षीय व्यापार 70 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंच रहा है, लेकिन हम आराम से नहीं बैठ सकते, हमें आगे बढ़ना होगा और संतुलन बनाना होगा। भारत का रूस को निर्यात 2024-25 में 4.9 अरब अमेरिकी डालर रहा, जबकि आयात 63.8 अरब अमेरिकी डॉलर था। इससे व्यापार घाटा करीब 59 अरब अमेरिकी डालर रहा। दोनों पक्षों ने 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि भारत सेवा क्षेत्र में भी रूस को बड़ी पेशकश कर सकता है।

रूसी संघ के राष्ट्रपति कार्यालय के डिप्टी चीफ आफ स्टाफ मैक्सिम ओरेश्किन ने बैठक में कहा कि रूस के आयात में भारत की हिस्सेदारी दो फीसद से भी कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। ओरेश्किन ने कहा कि अधिक संतुलित व्यापार के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत छह प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ा सकता है जिनमें कृषि, औषधि, दूरसंचार उपकरण, औद्योगिक कल-पुर्जे एवं मानव संसाधन शामिल हैं।

गोयल ने उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित भारत-रूस व्यापार मंच की बैठक में कहा द्विपक्षीय व्यापार 70 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंच रहा है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा और संतुलन बनाना होगा। भारत का रूस को निर्यात 2024-25 में 4.9 अरब अमेरिकी डालर रहा, जबकि आयात 63.8 अरब अमेरिकी डॉलर था।

भारत, कनाडा ने व्यापार समझौते पर बातचीत की रूपरेखा पर चर्चा की

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (भाषा)।

2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डालर तक बढ़ाने का लक्ष्य।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने बुधवार को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की रूपरेखा, उद्देश्यों और तौर-तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्ष हाल ही में इस समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) कहा जाता है। इसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डालर तक बढ़ाना है।

गोयल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, कनाडा के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री सिद्धू के साथ सार्थक बातचीत हुई। हमने सीइपीए वार्ता शुरू करने की तैयारियों के तहत समग्र दृष्टिकोण, रूपरेखा, व्यापक उद्देश्यों और तौर-तरीकों पर शुरुआती और व्यापक चर्चा की। उन्होंने अगले साल कनाडा में एक उच्च-स्तरीय व्यापार और निवेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने पर भी सहमति जताई।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में, कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई थी। उसके बाद कनाडा ने भारत के साथ समझौते पर बातचीत रोक दी थी।

सीईपीए एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है, जिसके तहत दो देश अपने बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को या तो काफी कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। ये समझौते कुशल पेशेवरों की आवाजाही के मानदंडों को भी आसान बनाते हैं और निवेश आकर्षित करते हैं।

एक अध्ययन से खुलासा | चिंताजनक | कुपोषण, कम वजन व कमजोरी मौत का प्रमुख कारण

दुनिया भर में 2023 में 10 लाख बच्चों की हुई मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

दुनिया भर में 2023 में करीब दस लाख बच्चों की पांच साल की उम्र पूरी होने से पहले ही मौत हो गई। कुपोषण, कम वजन, ठिगनापन और कमजोरी जैसे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को इसका प्रमुख कारण बताया गया है। एक नए अध्ययन के अनुसार इनमें से एक लाख से अधिक मौत भारत में हुईं।

'द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल' में प्रकाशित निष्कर्ष बताते हैं कि ह्यबच्चे के विकास में विफलताह्व के कारण उक्त आयु वर्ग के बच्चों की हुई मौतों की सबसे अधिक संख्या नाइजीरिया में (1,88,000) दर्ज की गई जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 50,000 से अधिक मौत दर्ज की गईं। इसी के साथ कांगों भारत से एक पायदान नीचे तीसरे स्थान पर रहा।

'बाल विकास विफलता' से कई बीमारियों से मृत्यु और दिव्यांगता का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें निचले श्वसन तंत्र (एलआरटीआइ) के संक्रमण, पेचिश संबंधी रोग, मलेरिया और खसरा शामिल हैं। एलआरटीआइ एक संक्रमण है जो श्वासनली से नीचे फेफड़ों तक के वायुमार्ग को प्रभावित करता है। विश्लेषण में 'ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज स्टडी 2023' के आंकड़ों का उपयोग किया गया, जो 204 देशों और क्षेत्रों में बीमारियों, चोटों और जोखिम कारकों के कारण होने वाले स्वास्थ्य नुकसान का आकलन करने वाली नवीनतम रपट है।

वैश्विक स्तर पर बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से होने वाली मौतों में गिरावट दर्ज की गई है – 2000 में यह संख्या 27.5 लाख थी, जो 2023 में घटकर 8 लाख रह गई। हालांकि, शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया अब भी गंभीर और केंद्रित प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव झेल रहे हैं, जहां पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में क्रमशः छह लाख से अधिक और 1.65 लाख मौत हुई हैं।

अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी आफ वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट फार हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्युएशन के प्रोफेसर और अध्ययन के सह-लेखक बॉबी रीनर ने बताया, बच्चों के विकास में विफलता के पीछे के कारण जटिल और संचयी हैं, जिनमें कुपोषण, खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छता की कमी और युद्ध जैसी स्थितियां शामिल हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालय ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज अध्ययन का समन्वय करता है।

> 'द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल' में प्रकाशित निष्कर्ष बताते हैं कि 'बच्चे के विकास में विफलता' के कारण उक्त आयु वर्ग के बच्चों की हुई मौतों की सबसे अधिक संख्या नाइजीरिया में (1,88,000) दर्ज की गई जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 50,000 से अधिक मौत दर्ज की गई। इसी के साथ कांगों भारत से एक पायदान नीचे तीसरे स्थान पर रहा।

केंद्रीय भूजल बोर्ड की रपट में खुलासा

नौ राज्यों में भूजल की गुणवत्ता खराब, स्तर मिला खतरनाक

राकेश शर्मा
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

बढ़ते जल प्रदूषण के साथ भूजल की गुणवत्ता भी लगातार खराब हो रही है। देश के नौ राज्यों में भूजल में भारी प्रदूषण, कई क्षेत्रों में खारापन, नाइट्रेट और भारी धातुएं मानक से ऊपर पाए गए हैं। इसका खुलासा केंद्रीय भूजल बोर्ड की रपट से हुआ है।

मृदा, खाद्य शृंखला और जलीय जीवन को पहुंचा सकती है भारी नुकसान।

रपट के मुताबिक, जून 2024 से मार्च 2025 के बीच पानी में नाइट्रेट, फ्लोराइड, कुल कठोरता, क्रोमियम, मैगनीज, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, आर्सेनिक, सेलेनियम, कैडमियम, सीसा तथा यूरेनियम जैसे तत्त्व मानक से अधिक पाए गए। यह समस्या आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में पाई गई। इन नौ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में लवणता, नाइट्रेट तथा भारी धातुओं से संबंधित मानकों से अधिक मिले हैं। वहीं पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों में आयरन, मैगनीज और आर्सेनिक की मात्रा अधिक मिली है। चिकित्सकों का कहना है कि भू जल में मानक से अधिक धातु के होने से न केवल पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि लंबे समय में जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। इसमें कैंसर, त्वचा रोग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र रोग, गुर्दा खराब, हृदय रोग सहित कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा दूषित भूजल सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने पर मिट्टी को प्रदूषित करती है। प्रदूषित मिट्टी में उगने वाली फसलों और पौधों में ये धातु अवशोषित होकर मानव व जानवरों की खाद्य शृंखला में प्रवेश कर सकती हैं। वहीं दूषित पानी जलीय जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी रोकथाम के लिए भूजल बोर्ड राज्यों एवं संबंधित एजंसियों को पाक्षिक जल गुणवत्ता सतर्कता जारी करता है।

सूत्रों का कहना है कि इस चेतावनी के जारी होने से संबंधित राज्य सरकार और एजंसियों को तुरंत जांच के लिए नमूने एकत्रित करना, स्थानीय जल चेतावनी जारी करना, वैकल्पिक पेयजल स्रोतों का प्रावधान करना और तत्काल शमन उपाय के लिए कहा जाता है। ताकि किसी भी संभावित जल-संकट या स्वास्थ्य जोखिम की स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। कृषि-प्रधान राज्यों में नाइट्रेट की समस्या उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जुड़ी मानी जा रही है, जबकि औद्योगिक क्षेत्रों में भारी धातुओं की मौजूदगी प्रदूषण नियंत्रण तंत्र में कमी को दर्शाती है

> *पहचाने गए 340 खतरनाक केंद्र*
>
> जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि सीजीडब्ल्यूबी की सालाना भू जल गुणवत्ता रपट 2025 के अनुसार, मानसून से पहले और मानसून के बाद 2024 के दौरान बोर्ड ने 26 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से आर्सेनिक के लिए 3415 भू जल नमूने और लेड के लिए 21 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों से 2537 नमूने इकट्ठा करके उनका मूल्यांकन किया। इसमें पता चला कि 3415 में से 123 नमूने (3.6 फीसद) आर्सेनिक के लिए 10 पीपीबी की तय मानक से ज्यादा थे, जबकि 2,537 में से 24 नमूने (0.95 फीसद), लेड के लिए 0.01 एमजी प्रति लीटर की तय मानक से ज्यादा थे।

'भारत और सऊदी अरब के बीच संसदीय मैत्री समूह का होगा गठन'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर

जल्द ही भारत-सऊदी अरब के बीच संसदीय मैत्री समूह का गठन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

ओम बिरला

यह फैसला सऊदी अरब साम्राज्य की शूरा काउंसिल की ओर से सऊदी-भारत संसदीय मैत्री समिति के चेयरमैन, मेजर जनरल अब्दुल रहमान बिन सनहत अल-हरबी के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया। यह प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के लिए नई दिल्ली पहुंचा था। बिरला ने कहा कि संसदीय कूटनीति राष्ट्रों के बीच महत्त्वपूर्ण सेतु का काम करती है, जो गहरी समझ का विकास, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और मजबूत संस्थागत सहयोग को संभव बनाती है।

उन्होंने दोनों देशों की संसदीय समितियों के बीच नियमित संवाद का आह्वान किया। भारतीय प्रवासियों ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और सऊदी अर्थव्यवस्था में अपने योगदान के माध्यम से विश्व स्तर पर सम्मान अर्जित किया है। इस तरह के सांस्कृतिक आदान-प्रदान लोगों के बीच संबंधों को और गहरा करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिष्टमंडल की यात्रा द्विपक्षीय एवं संसदीय संबंधों को और मजबूत करेगी तथा विविध क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। मेजर जनरल अब्दुल रहमान ने भारत के हज यात्रियों के साथ हुई हालिया त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

रूसी शिक्षा एजंसी की नई पहल

शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय शाखा शुरू की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

रूस और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने और भारतीय छात्रों को रूसी विश्वविद्यालयों में दाखिले में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रूस एजुकेशन एजंसी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपनी एक शाखा शुरू की। यह एजंसी सिनर्जी कारपोरेशन और इनोप्रैक्टिका.इंडिया की संयुक्त पहल है।

एजंसी के अनुसार, नई दिल्ली स्थित रूसी शिक्षा एजंसी भारतीय आवेदकों के लिए समर्पित सहायता केंद्र के रूप में कार्य करेगी, जो शैक्षणिक कार्यक्रम और विश्वविद्यालय चुनने, प्रवेश प्रक्रियाओं को पूरा करने, वीजा प्राप्त करने और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रबंधन में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस पहल से भारतीय छात्रों के लिए रूस में उच्च शिक्षा प्राप्त करना सरल होगा। सिनर्जी कारपोरेशन के अध्यक्ष वादिम लोबोव ने कहा, 'रूसी विश्वविद्यालयों से स्नातक होने वाले कई भारतीय छात्र हमारे देशों और संस्कृतियों के बीच सच्चे दोस्त बने हैं।' रूसी विश्वविद्यालय सोवियत उच्च शिक्षा प्रणाली की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, जिसे भारत में व्यापक सम्मान मिला।

भारत और रूस के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच माल एवं वाहनों का आवाजाही के संबंध में आगमन-पूर्व सूचना के आदान-प्रदान पर सहयोग के लिए बृहस्पतिवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी और रूस की संघीय सीमा-शुल्क सेवा की उप प्रमुख तातियाना मकुशीवा ने सम्मेलन के पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

सिनर्जी कारपोरेशन के अध्यक्ष वादिम लोबोव ने कहा, 'रूसी विश्वविद्यालयों से स्नातक होने वाले कई भारतीय छात्र हमारे देशों और संस्कृतियों के बीच सच्चे दोस्त बने हैं।'

शिखर सम्मेलन से पहले भारत व रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच महत्त्वपूर्ण वार्ता हुई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

भारत और रूस ने गुरुवार को अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का विस्तार करने का संकल्प जताया, जिसमें नई दिल्ली ने अपनी लड़ाकू क्षमता को मजबूत करने के लिए मास्को से एस-400 मिसाइल प्रणालियों के अतिरिक्त बैच खरीदने में गहरी रुचि दिखाई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की एक महत्त्वपूर्ण बैठक में दोनों पक्षों ने समग्र रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। यह बैठक 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ शुक्रवार को शिखर वार्ता करेंगे। बेलौसोव के साथ बैठक में सिंह ने घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों के लिए स्वदेशी रक्षा उद्योग की क्षमता निर्माण के वास्ते भारत का दृढ़ संकल्प दोहराया, साथ ही विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में भारत-रूस सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर प्रकाश डाला।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने दोहराया कि भारत-रूस संबंध विश्वास की गहरी भावना, समान सिद्धांतों और आपसी सम्मान पर आधारित हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत ने रूसी पक्ष को सतह से हवा में मार करने वाली एस-400 मिसाइल प्रणालियों के अतिरिक्त बैच खरीदने में अपनी रुचि से अवगत कराया है, क्योंकि 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान ये प्रणाली बहुत प्रभावी साबित हुई थी। अक्तूबर 2018 में, भारत ने रूस के साथ एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की पांच इकाइयों को खरीदने के लिए पांच अरब अमेरिकी डालर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अनुबंध पर आगे बढ़ने पर अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं। 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान एस-400 प्रणालियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वर्ष 2009 से अब तक अमेरिका ने 18,822 भारतीयों को किया निर्वासित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि अमेरिका ने वर्ष 2009 से अब तक कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है, जिनमें जनवरी 2025 से अब तक निर्वासित किए गए 3,258 भारतीय शामिल हैं। उच्च सदन में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए जयशंकर ने कहा कि मानव तस्करी के मामलों की जांच राज्यों के साथ राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने भी की है, जिनमें पंजाब में सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं।

उन्होंने बताया कि 2009 से अब तक कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजा गया है। वर्ष 2023 में 617 भारतीयों को और 2024 में 1,368 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया गया। जनवरी 2025 से अब तक कुल 3,258 भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने भारत निर्वासित किया है।

इनमें से 2,032 भारतीय (लगभग 62.3 फीसद) नियमित वाणिज्यिक उड़ानों से और शेष 1,226 भारतीय (37.6 फीसद) अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आइसीई) या सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा संचालित चार्टर उड़ानों से लौटे हैं। जयशंकर ने बताया कि एनआइए ने कुछ वर्ष पहले मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की थी, जिसे मानव तस्करी के मामलों की जांच का प्राधिकार प्राप्त है। एनआइए ने मानव तस्करी के 27 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की है, जिनमें 169 गिरफ्तारियां हुई हैं और 132 व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए गए हैं। एनआइए ने हरियाणा और पंजाब में सात अगस्त को दो प्रमुख तस्करों को और हिमाचल प्रदेश में दो अक्तूबर को दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। राज्यों में पंजाब में मानव तस्करी के सर्वाधिक मामले हैं।

'पंजाब सरकार ने एसआइटी और तथ्य-जांच समिति गठित की है। 58 अवैध ट्रैवल एजंटों के खिलाफ 25 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में 2,325 मामले और 44 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। इन मामलों में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात ने भी एक महत्त्वपूर्ण तस्कर को गिरफ्तार किया है।

विदेश मंत्रालय, अमेरिकी आइसीई/सीबीपी की निर्वासन प्रक्रिया के दौरान भारतीय नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु अमेरिकी पक्ष के साथ निरंतर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए हथकड़ी-बेड़ियों के उपयोग को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष दर्ज कराई है। पांच फरवरी की निर्वासन उड़ान के बाद से महिलाओं और बच्चों को बेड़ियां पहनाने की कोई घटना मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आई है।

जयशंकर ने बताया कि 2009 से अब तक कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजा गया है। वर्ष 2023 में 617 भारतीयों को और 2024 में 1,368 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया गया। जनवरी 2025 से अब तक कुल 3,258 भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने भारत निर्वासित किया है। इनमें से 2,032 भारतीय वाणिज्यिक उड़ानों से और शेष 1,226 संचालित चार्टर उड़ानों से लौटे हैं।

विदेश मंत्रालय, भारतीय नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु अमेरिकी पक्ष के साथ निरंतर बातचीत कर रहा है। मंत्रालय ने विशेषकर महिलाओं व बच्चों के लिए हथकड़ी-बेड़ियों के उपयोग को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष दर्ज कराई है।

अर्जुन एरिगैसी ने आनंद को हराकर यरुशलम मास्टर्स का खिताब जीता

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने फाइनल में हमवतन और पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर यरुशलम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। इन दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआती रैपिड गेम ड्रा किए। इसके बाद एरिगैसी ने पहले ब्लिट्ज टाईब्रेक मैच में सफेद मोहरों से जीत हासिल कर निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। 'चेसबेस डाट काम' की रपट के अनुसार, 22 वर्षीय एरिगैसी दूसरे ब्लिट्ज मुकाबले में भी जीत हासिल करने के करीब पहुंच गए थे लेकिन आखिर में उन्हें ड्रा से संतोष करना पड़ा, लेकिन यह उनके लिए 2.5-1.5 से मुकाबला और खिताब जीतने के लिए पर्याप्त था।

खिताब जीतने के बाद अर्जुन एरिगैसी ने बताया कि यह जीत उनके लिए असान नहीं थी। पीटर स्विडलर और फिर आनंद के खिलाफ मुकाबले तनावपूर्ण थे। विश्वनाथन आनंद ने दो बार के विश्व चैंपियनशिप दावेदार इयान नेपोमनियाची को सेमीफाइनल में हराया, जबकि अर्जुन ने पीटर स्विडलर को शिकस्त दी थी। इस जीत ने अर्जुन को थोड़ी राहत दी है, क्योंकी हाल ही में उन्हें फीडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। चीन के वेई यी ने अर्जुन को शिकस्त दी थी। दो साल पहले 2023 में उनके साथी प्रग्गनानंदा ने उन्हें हराया था।

विश्वनाथन आनंद और अर्जुन एरिगैसी दोनों ने 12-पुरुष राउंड राबिन स्पर्धा में शीर्ष चार स्थानों पर रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया था। स्विडलर ने प्रारंभिक राउंड-राबिन चरण में 8/11 के प्रदर्शन के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था, जबकि आनंद और अर्जुन 7.5/11 के स्कोर के साथ नेपोमनियाची के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर थे। इस जीत के साथ एरिगैसी को 55,000 अमेरिकी डालर, जबकि आनंद को 35,000 अमेरिकी डालर की पुरस्कार राशि मिली। जेरूसलम मास्टर्स के लिए राउंड-राबिन प्रारूप में 12 खिलाड़ी भाग लेते हैं, जिसमें से शीर्ष चार खिलाड़ी प्लेआफ में पहुंचते हैं।

शतरंज

इस जीत के साथ एरिगैसी को 55,000 अमेरिकी डालर, जबकि आनंद को 35,000 अमेरिकी डालर की पुरस्कार राशि मिली। विश्वनाथन आनंद और अर्जुन एरिगैसी दोनों ने 12-पुरुष राउंड राबिन स्पर्धा में शीर्ष चार स्थानों पर रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया था। अर्जुन ने सेमीफाइनल में पीटर स्विडलर को शिकस्त दी थी।

यह जीत असान नही थी, सामने कई चुनौतियां थी : एरिगैसी

यरुशलम मास्टर्स का खिताब जीतने के बाद अर्जुन एरिगैसी ने कहा, 'यह जीत आसान नहीं थी। मेरे सामने कई चुनौतियां थी और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी नहीं कर पाया। इसके बावजूद खिताब हासिल करके मैं बहुत खुश हूं। आज के दोनों मुकाबले (पीटर स्विडलर और फिर आनंद के खिलाफ) काफी तनावपूर्ण रहे। आनंद सर के खिलाफ पहले गेम में हम दोनों ने मौके गंवाए। लेकिन मुझे लगता है कि ब्लिट्ज में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया।' गेम 1 में नियंत्रण खोने के बारे में उन्होंने कहा, मैं थोड़ा चिंतित था। मुझे वापस लड़ना था और मैं गेम में वापसी करने की कोशिश कर रहा था।

Source- दैनिक जागरण

वीवीआइपी की सरकारी गाड़ियों का अब नहीं लगेगा टोल-टैक्स

सरकारी गाड़ियों पर लगाना होगा छूट वाला फास्टैग

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : सांसद-विधायकों समेत अन्य वीवीआइपी की सरकारी गाड़ियों को अब टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ी पहल की है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी संबंधित वीवीआइपी को पत्र लिखकर अपनी पात्र सरकारी गाड़ियों पर छूट वाला फास्टैग (एक्जेम्प्टेड फास्टैग) शीघ्र लगवाने को कहा है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के एक्जेम्प्शन (छूट) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा।

परिवहन मंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी पात्र वाहनों को तीन महीने के अंदर एनएचएआइ के एक्जेम्प्शन (छूट) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर कराना होगा। राज्य में वर्तमान में सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, मुख्य सचिव समेत कई वीवीआइपी की सरकारी गाड़ियां इस पोर्टल पर रजिस्टर हैं, जिसके कारण वह टोल प्लाजा पर बिना रुके निकल जाती हैं। मंत्री ने सभी से अपील की है कि निर्धारित समय के अंदर अपने वाहनों की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कराकर छूट वाला फास्टैग लगवा लें।

परिवहन मंत्री ने कहा कि वीवीआइपी की गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रोकने से कई बार महत्वपूर्ण बैठक या कार्यक्रम में देरी हो जाती है। उनकी सहूलियत और कीमती समय की बचत के लिए यह व्यवस्था की गई है। विभाग ने सभी संबंधितों को अलग-अलग पत्र भेजकर भी व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, ताकि आगे किसी तरह की असुविधा न हो।

बड़ी पहल

- एनएचएआइ के पोर्टल पर करना होगा निबंधन
- एनएचएआइ के एक्जम्शन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा

श्रवण कुमार • जागरण आर्काइव

अभी वीवीआइपी गाड़ियों को मिलती है टोल टैक्स से छूट

- मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, लोकसभा में विपक्ष के नेता
- सांसद और विधायक (सरकारी गाड़ी पर)
- उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश
- राज्य के सभी मंत्री, वर्तमान एवं पूर्व विधायक-विधान पार्षद
- बिहार विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री

नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : जदयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार बिहार विधानसभा के निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। उनके लिए चार प्रस्ताव आए थे। सम्राट के अलावा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं लोजपा (रा) विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने भी प्रस्ताव दिया था। सम्राट के प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी गई। नरेंद्र नारायण यादव 1995 से लगातार मधेपुरा जिला के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आठवीं जीत दर्ज की। वे 17 वीं विधानसभा में भी उपाध्यक्ष थे। समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक नरेंद्र नारायण यादव राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। आलमनगर प्रखंड के प्रमुख पद पर रहते हुए 1995 में विधानसभा का चुनाव लड़े। तब से लगातार जीत रहे हैं।

नरेंद्र नारायण यादव

विधान परिषद में विपक्ष का वाकआउट

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : बिहार विधान परिषद में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए संशोधन प्रस्ताव के बारे में बोलने का समय न दिए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने वाकआउट कर दिया। अभिभाषण पर जदयू की रीना देवी ने धन्यवाद प्रस्ताव लाया जिसका भाजपा के डा. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से समर्थन किया। इसके बाद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए आमंत्रित किया। इसपर विपक्ष ने आपत्ति जताई कि पहले उनके संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। सभापति ने कहा कि संशोधन प्रस्ताव समेकित रूप से ले लिया गया है। इसपर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। सभापति ने कहा कि सदन के नेता के बोलने के बाद जरूरत हुई तो इसपर बोलने का मौका दिया जाएगा। यह आसन का विशेषाधिकार है। इस दौरान मुख्यमंत्री बोलना शुरू कर चुके थे। इसके बाद राबड़ी देवी समेत विपक्ष के सदस्य वाकआउट करते हुए सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन ने संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। वहीं धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

विधान परिषद परिसर में गुरुवार को संवाददाताओं से बात करतीं पूर्व मुख्यमंत्री रावड़ी देवी, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी व अन्य • जागरण

बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला विधानसभा में उठा

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संतोष वर्मा की ब्राह्मण बेटियों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला विधानसभा में भी गूंजा। लोजपा (रा) के विधायक राजू तिवारी ने विधानसभा में यह मामला उठाया और इस टिप्पणी का दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से मांग की कि आइएएस अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज हो साथ ही उन पर कठोर कार्रवाई भी हो। राजू तिवारी ने कहा कि वे ब्राह्मण जाति से आते हैं। एक आइएएस अधिकारी हैं संतोष वर्मा, जिन्होंने पद की मर्यादा को दरकिनार करते हुए ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आसन, मुख्यमंत्री से मांग की कि ऐसी टिप्पणी करने वाले अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

विधानपरिषद की पहली पाली में चार संशोधन नियमावली को सदन की मेज पर रखा गया। मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली और बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त संशोधन नियमावली की एक-एक प्रति सेदन की मेज पर रखी। वहीं मंत्री प्रमोद कुमार ने अग्निशमन सेवा संशोधन नियमावली और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बिहार अमीन संवर्ग नियमावली की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी।

बीआइआइपीपी-2025 औद्योगिक विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा : डा. जायसवाल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना: उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार अब औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बीआइआइपीपी-2025) गेम चेंजर साबित होगा। वे गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य में स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसके लिए विश्वविद्यालयों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा। बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को सुरक्षा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया कराएगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि जो लोग सब्सिडी लेकर राज्य

दिलीप जायसवाल ● जागरण आर्काइव

में इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसे मैं उद्योग नहीं मानता। जो लोग खुद का पैसा लगाकर उद्योग लगाकर आम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं वास्तव में वही उद्योग है। बिहार लंबे समय से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहा है, अब औद्योगिकीकरण के तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज न केवल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन प्रदान करता है, बल्कि राज्य की आर्थिक संरचना को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है। इस पैकेज के तहत निवेशकों को तीन मुख्य योजनाओं का विकल्प दिया गया है जो निवेश की राशि, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित है। डा. जायसवाल ने कहा कि बीआइआइपीपी-2025 योजना के तहत एक सौ करोड़ के निवेश और एक हजार प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने वाले उद्यमियों को 10 एकड़ भूमि मुफ्त या एक रुपये प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध कराई जाएगी।

स्वागत है राष्ट्रपति पुतिन, भारत ने बिछाए पलक पांवड़े

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकाल तोड़कर रूसी राष्ट्रपति की हवाई अड्डे पर की अगवानी, पालम एयरपोर्ट से एक ही कार में रवाना हुए दोनों नेता

जयाकांत रंजन ● जागरण

नई दिल्ली : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने बहुप्रतीक्षित भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने और दुनिया के भू-राजनीतिक समीकरण में 360 डिग्री बदलाव के साथ भारत के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तल्खी भरे रिश्तों के बीच उनकी इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अपने सदाबहार दोस्त को यहां पाकर भारतीय जनमानस आह्लादित है। 27 घंटे के पुतिन के इस दौरे पर पहुंचने के बाद सामान्य प्रोटोकाल तोड़कर भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पालम एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनकी आगवानी करना और उनसे गले मिलना, देशवासियों के उन्हीं मनोभावों की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में पूरा देश उत्साहित है। कहीं यज्ञ, कहीं हवन तो कहीं भारत-रूस मित्रता की कव्वालियां कही-सुनी जा रही हैं। सचमुच पूरा देश कह रहा है, राष्ट्रपति पुतिन आपका हमारे देश में स्वागत है।

चार वर्षों बाद भारत की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। शाम 6.45 बजे उनका विमान दिल्ली स्थित पालम एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद दोनों नेता जापानी कार कंपनी टोयोटा की एसयूवी से एक साथ हवाई अड्डे से निकले। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति पुतिन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सात, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर पहुंचे। वहां पर दोनों नेताओं ने कुछ गिने-चुने अधिकारियों के साथ रात्रि भोज किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास को चमकदार लाइटों और फूलों से सजाया गया था।

पुतिन का स्वागत करने के बाद मोदी ने 'एक्स' पर लिखा कि, 'अपने मित्र पुतिन का भारत में स्वागत करके काफी खुशी हुई। आज शाम और कल हमारे बीच होने वाले विमर्श का मैं इंतजार कर रहा हूं। भारत-रूस की मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इसने हमारे दोनों देशों के लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया है।' मोदी और पुतिन के बीच रात्रिभोज के दौरान होने वाली बातचीत के बारे में देर रात खबर लिखे जाने तक आधिकारिक या गैर-आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन बताते हैं कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत-रूस संबंधों से जुड़े मुद्दों के अलावा अन्य बहुराष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई।

साथ ही शुक्रवार को होने वाले 23वें भारत-रूस सालाना सम्मेलन में होने वाले कुछ समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से यही बताया गया कि दोनों नेताओं ने जुलाई, 2024 में भी सालाना शिखर सम्मेलन से पहले निजी तौर पर आपसी बातचीत की थी। यही नहीं शंघाई सहयोग संगठन की चीन के तियानजिन में हुई बैठक के दौरान भी पुतिन की कार में दोनों नेताओं ने एक साथ यात्रा की थी।

राष्ट्रपति पुतिन की यह भारत यात्रा मौजूदा वैश्विक हालात और भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अहम है। यूक्रेन से युद्ध के बाद भारत ने रूस से काफी ज्यादा मात्रा में कच्चे तेल की खरीद की है। इससे अमेरिका व यूरोपीय देश काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि भारत जो भुगतान करता है, उसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में करता है।

स्वागत पुतिन » पेज 9

सदाबहार दोस्त

- पीएम आवास पर रात्रि भोज के दौरान हुई दोनों में चर्चा
- अपने मित्र पुतिन का स्वागत करके काफी खुशी हुई : पीएम

राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की प्रति उपहार में दी। गीता के उपदेश दुनियाभर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं।

– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव

दोनों देशों के बीच यूरेशियन इकोनमिक यूनियन के साथ नई दिल्ली के प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा होने की संभावना है। वार्ता के दौरान उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन, मोदी को यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका की नई कोशिशों के बारे में बताएंगे।

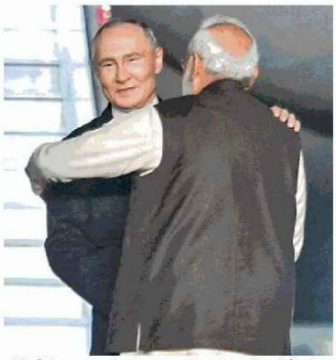

नई दिल्ली स्थित पालम हवाईअड्डे पर गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गले लगाकर स्वागत करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। ● आइएएनएस

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज का कार्यक्रम

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत करेंगी।
- पुतिन राजघाट जाकर राष्ट्रपिता गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे।
- हैदराबाद हाउस में सीमित वार्ता, फिर प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता।
- हैदराबाद हाउस में ही मोदी प्रतिनिधिमंडल के लिए लंच आयोजित करेंगे।
- दोनों नेता फिक्की और सेसकांग्रेस के संयुक्त कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
- राष्ट्रपति मुर्मु पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगी। रात्रि करीब 9 बजे पुतिन भारत से रवाना हो जाएंगे।

कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की संभावना

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि रात्रिभोज के दौरान हुई चर्चा से ही आधिकारिक वार्ता की भूमिका तैयार होगी। शुक्रवार को भारत और रूस के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसमें एक समझौता मोबिलिटी यानी एक दूसरे के प्रशिक्षित श्रम को काम करने का अधिकार व मौका देने से संबंधित होगा। इससे रूस के ढांचागत क्षेत्र में हजारों भारतीयों को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। जहाजरानी, हेल्थकेयर, उर्वरक और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी भारत व रूस के बीच समझौता होने की संभावना है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भी अहम बातचीत होगी, लेकिन किसी खास रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर समझौता होने की उम्मीद कम है।

समस्या जानने के लिए सीधे निवेशकों से मिलेंगे मुख्य सचिव

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: उद्योग और निवेश को गति देने के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हर गुरुवार को 'उद्योग वार्ता' करेंगे, जिसमें निवेशक बिना किसी पूर्व अनुमति के सीधे उनसे मिलकर अपनी समस्याएं और सुझाव रख सकेंगे। इसकी शुरुआत गुरुवार को मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग स्थित मुख्य सचिव कोषांग में हुई। सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक मुख्य सचिव ने देश-विदेश के आठ निवेशकों से मुलाकात कर कार्ययोजना पर चर्चा की। निवेशकों के अईडिया को सुना और और इनके समाधान के लिए मौके पर ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए। वाशिंगटन डीसी स्थित टेन्सर एनालिटिक्स के संस्थापक किसलय सिंह ने डेटा इंटीग्रेशन क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई। टाइगर एनालिटिक्स के सीईओ महेश कुमार ने बिहार को टेक हब बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के क्षेत्र में सहयोग की बात कही। इसी तरह एविसिस सर्विसेज के सीईओ हर्षवर्धन कुमार, ब्रांड रणनीतिकार सचिन भारद्वाज, डालमिया सीमेंट के राजेश कुमार, मुंबई की सीलिंक फायर एंड सेफ्टी के सुशील के. सिंह और जेनेसिस कंपनी के गितेश विश्वास समेत कई उद्योगपतियों ने निवेश की प्रतिबद्धता जताई।

प्रत्यय अमृत

पांच वर्षों में और तेज होगी विकास की गति

मुख्यमंत्री बोले बिहार बनेगा अग्रणी राज्य 2005 से हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ बिहार का विकास

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश को बिहार के विकास के लिए सकारात्मक और ऐतिहासिक संदेश बताया है। उन्होंने अपनी सरकार के दो दशक लंबे विकास अभियान का विस्तृत लेखा-जोखा पेश किया। साथ ही कहा कि उनका एक मात्र उद्देश्य है बिहार को अग्रणी राज्य बनाना। आने वाले पांच वर्षों में राज्य के विकास की गति और तेज होगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को पहले विधानसभा और बाद में विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 से लगातार बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहा हूं और आगे भी हमारा एकमात्र उद्देश्य बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और भारी बहुमत देकर एनडीए सरकार पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि आज के बिहार में तनाव, विभाजन और टकराव की गुंजाइश बेहद कम रह गई है। राज्य में शांति व सद्भाव का माहौल और भी मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य में बचे हुए 77 हजार नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा नहीं देनी होगी। मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बना दिया जाएगा। अभी तक बीपीएससी की ओर से तीन परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। नियोजित शिक्षकों को पांच परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बनने का अवसर दिया गया है। सभी शिक्षकों की नियुक्ति के बाद राज्य में शिक्षकों की संख्या 5.20 लाख हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी-फरवरी 2025 तक उनके द्वारा जिलों के भ्रमण के दौरान 430 नई योजनाओं की घोषणाएं की गई थीं। इन सभी नई योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। काम भी जल्द पूरा करा लिया जाएगा। सरकार अगले पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत 1.56 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेज दिए गए हैं। बाकी महिलाओं के खाते में भी राशि भेज दी जाएगी। रोजगार करने वाली इन महिलाओं को दो लाख और भी दिए जाएंगे।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को पंचायत, नगर निकाय में आरक्षण, पुलिस समेत अन्य नियुक्तियों में 35 प्रतिशत आरक्षण, जीविका समूह गठन, कब्रिस्तान और मंदिरों की घेराबंदी, मदरसों को सरकारी हाई स्कूल का दर्जा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 11 सौ रुपये करने जैसे उदाहरण भी दिए।

77 हजार नियोजित शिक्षकों को नहीं देनी होगी बीपीएससी परीक्षा

- सभी शिक्षकों की नियुक्ति के बाद 5.20 लाख हो जाएगी राज्य में शिक्षकों की संख्या
- 1.56 करोड़ महिलाओं को भेजे गए हैं 10-10 हजार, बाकी महिलाओं को राशि जल्द मिलेगी

विधानमंडल के गेट पर लोगों का अभिवादन करते सीएम नीतीश कुमार • जागरण

पीएम का मैं नमन करता हूं आप भी करें : सीएम

बिहार के विकास में केंद्र के सहयोग की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 और 2025 के बजट में बिहार के लिए विशेष बजट का प्रविधान किया गया है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हाथ उठाकर नमन करता हं। उन्होंने विपक्ष को भी कहा कि आप लोग भी हाथ उठाकर प्रधानमंत्री का नमन करें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया। विपक्षी सदस्यों के हाथ न उठाने पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा जब हम साथ थे तो आप बात मान लेते थे। गड़बड़ किए तो छोड़ दिए। अब कभी उधर नहीं जाएंगे।

राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में 13 हजार करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव

ऊर्जा मंत्री ने कहा, निवेशकों को मिलेंगी सभी सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रोमोशन पालिसी 2025 के माध्यम से बिहार सरकार पूरे देश और विदेश से ऊर्जा निवेशकों को आमंत्रित कर रही है। ये नीतियां स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और देश के नेट जीरो लक्ष्य में राज्य को सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मेसर्स ग्रीनको इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स सन पैट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्षेत्र में 13 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन परियोजनाओं के निर्माण अवधि तथा संचालन अवधि में लगभग आठ हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा एवं क्षमतावर्धन होगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह तकनीक सरप्लस बिजली को पंप करके संचित करती है और मांग के अनुरूप समय पर बिजली उत्पादन के लिए जल प्रवाह का उपयोग करती है।

बिजेन्द्र प्रसाद यादव • जागरण आर्काइव

विद्युत भवन में हुई सुनवाई

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से एचटी/एलटीआइएस उपभोक्ताओं एवं निवेशकों की विद्युत-संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विद्युत भवन, पटना स्थित अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के कान्फ्रेंस हाल में ओपन हाउस बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों वितरण कंपनियों- नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार सहित सभी संबंधित वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विभिन्न उद्योगों, व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने समस्याएं रखी। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को विस्तार से सुना और तत्काल जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देश दिया।

जाति से आगे निकलती राजनीति

बद्री नारायण

विकास की राजनीति एवं कल्याणपरक योजनाओं ने भारतीय समाज में ऐसी आकांक्षाएं जगाई हैं, जो जाति एवं पंथ की परिधि को तोड़ रही है

बिहार विधानसभा चुनाव में राजग को अद्भुत विजय प्राप्त हुई। इसे अद्भुत इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इसमें सर्वसमाज की चुनावी भागीदारी मुखरता से अभिव्यक्त हुई। समाज के सभी हिस्सों-दलित, पिछड़ा, अगड़ा, महिला और युवाओं का सर्वाधिक मत एवं समर्थन राजग के घटक दलों को मिला। बिहार के 67 प्रतिशत ओबीसी में से अगड़े ओबीसी का 71 प्रतिशत तथा अति पिछड़े ओबीसी का 68 प्रतिशत मत राजग को मिला। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राजद के ठोस वोट बैंक माने जाने वाले यादव और मुस्लिमों के मतों का भी एक हिस्सा राजग को प्राप्त हुआ। महागठबंधन के पक्ष में मुस्लिम-यादव गोलबंदी इस चुनाव में कुछ कमजोर पड़ी। करीब 60 प्रतिशत दलितों ने राजग को चुना। 48 प्रतिशत महिलाओं और 46 प्रतिशत पुरुषों ने भी राजग को वोट दिया। इसी के साथ युवाओं के एक बड़े प्रतिशत ने भी राजग की विजय में बड़ी भूमिका निभाई। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में समाज के सभी आर्थिक वर्गों यथा उच्च वर्ग, मध्य वर्ग एवं निम्न आर्थिक वर्ग ने अपना सर्वाधिक समर्थन जदयू-भाजपा के गठबंधन को दिया।

बिहार का जनादेश भारतीय समाज एवं भारतीय जनतंत्र की मूल प्रवृत्ति में बड़े रूपांतरण का द्योतक है। इस रूपांतरण को चुनाव परिणाम के विश्लेषण से सहज ही समझा जा सकता है। चुनाव परिणाम ने दिखाया कि अस्मितापरक गोलबंदी की राजनीति अब धीरे-धीरे अपना प्रभाव खोती जा रही है। विशेष रूप से जातीय अस्मिताओं की राजनीति, जो जातियों के बीच जातिभाव का टकराव बढ़ाकर विकसित की जाती है। बिहार के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि जनता को अब उससे कुछ ज्यादा चाहिए। राजनीतिशास्त्री रजनी कोठारी ने एक बार कहा था कि राजनीति को जाति चाहिए और जाति को राजनीति। नए संदर्भ में अब यह कहना उचित होगा कि राजनीति जाति से आगे निकल रही है। बिहार में तो ऐसा होता हुआ साफ दिखा। जातीय अस्मिता की राजनीति का जो राजनीतिक दर्शन जातियों के बीच अपने बनाम पराए की अवधारणा पर टिका है, उसमें संवाद एवं सहकार का भाव विकसित हुआ है। बिहार के चुनाव को अगर जाति के आप्टिक्स से देखें तो भी ज्यादातर जातियों ने आपसी समझ एवं समायोजन विकसित कर वोट दिया।

नतीजों का यह निहितार्थ भी है कि धीरे-धीरे भारत की चुनावी राजनीति दशकों पुराने एंटी इनकंबेंसी यानी सत्ता विरोधी रुझान की अवधारणा को खारिज करती जा रही है। मतदाताओं के मानस में एंटी इनकंबेंसी की जगह प्रो इनकंबेंसी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसा विशेष रूप से उन दलों और गठबंधनों के लिए हो रहा है, जिन्होंने विकास की राजनीति को जनकल्याण की नीतियों के साथ जोड़कर उन्हें अपने प्रशासन के माध्यम से जमीन पर सफलता एवं ईमानदारी से उतारा है। बिहार में महिला मतों की राजग के पक्ष में गोलबंदी इसी रसायन का परिणाम है। यह वह रसायन है, जिसे अपनी-अपनी राजनीति में पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने विकसित किया है। इस राजनीतिक रसायन ने किसान, मजदूर, दलित, महिला और युवा सभी को प्रभावित किया।

अवधेश राजपूत

बिहार के जनादेश ने यह भी साबित किया कि विकास की राजनीति एवं कल्याणपरक योजनाओं ने भारतीय समाज में ऐसी आकांक्षाएं जगाई हैं, जिसने जाति एवं पंथ की दीवारों एवं अस्मितापरक भावनाओं की परिधि को तोड़कर भाजपा एवं राजग के पक्ष में बड़ा समर्थन तैयार किया। बिहार के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं से बने लाभार्थी वर्ग का हिस्सा बन चुका है। स्वाभाविक है कि उनमें से अधिकांश ने विधानसभा चुनावों में राजग को वोट दिया।

लाभार्थी चेतना की एक प्रवृत्ति यह होती है कि उसे सतत रूप से अपनी जरूरतों के अनुसार राज्य सत्ता से नया समर्थन पाने की चाह होती है। भाजपा एवं राजग ने लाभार्थी चेतना की इसी प्रवृत्ति को समझते हुए महिला रोजगार कार्यक्रम के तहत 10 हजार रुपये का वित्तीय समर्थन देना शुरू किया, जिसने महिला मतदाताओं को बड़ी संख्या में राजग के पक्ष में जोड़ा। इस प्रकार तमाम धारणाओं को ध्वस्त करते हुए गरीब सामाजिक समूहों में लाभार्थी अस्मिता विकसित होती जा रही है। भारतीय राज्य और समाज में आए इन नए परिवर्तनों ने हमें राजनीति को समझने के पुराने तौर-तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव ने भारतीय मतदाताओं के स्तर पर आकार ले रहे नए परिवर्तनों से भी हमारा साक्षात्कार कराया। इन चुनावों ने दर्शाया कि सामाजिक न्याय की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ है। सामाजिक राजनीति का दावा करने वाले राजनीतिक दलों की इस बार दाल नहीं गली। बिहार के दलित और पिछड़े वर्ग ने सामाजिक न्याय की अपनी आकांक्षा के लिए राजग पर विश्वास दिखाया। यह इसलिए भी संभव हुआ, क्योंकि सामाजिक न्याय की अवधारणा अब व्यापक हुई है। वह अब क्षैतिज विस्तार ले रही है। इसमें न केवल आरक्षित वर्ग वरन हाशिए पर बसे समुदायों में सरकारी योजनाओं के प्रभाव में आगे बढ़ने की आकांक्षा भी शामिल हुई है। पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय की नई अवधारणा, जिसे समग्र सामाजिक न्याय की अवधारणा कहा जा सकता है, विकसित की है। बिहार की जनता ने इसी संकल्पना पर मुहर लगाई।

राजनीति अंततः नेता एवं नेतृत्व केंद्रित होती है। नरेन्द्र मोदी एवं नीतीश कुमार पर विश्वास, अमित शाह की रणनीति और सांगठनिक दिशा दृष्टि, धर्मेंद्र प्रधान जैसे संगठकों का आधार तल पर किया गया कार्य, भाजपा-जदयू नेताओं के जनता से जुड़ाव ने राजग को विजय दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। यह भी याद रहे कि इतनी बड़ी विजय केवल जातीय समीकरणों से ही नहीं प्राप्त होती। इसके लिए कोई भावनात्मक आधार भी चाहिए। इस चुनाव का भावनात्मक आधार मोदी और नीतीश पर भरोसा और उनके प्रति सहानुभूति भाव, लोगों में बढ़ रही विकास की आकांक्षा रही। बिहार की अस्मिता को सम्मान दिलाने के भाव ने भी अपना असर दिखाया।

(लेखक टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, मुंबई के कुलपति हैं)

response@jagran.com

फिच ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत किया

रेटिंग एजेंसी ने कहा-उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी और जीएसटी सुधारों के साथ बेहतर धारणा के चलते वृद्धि अनुमान बढ़ाया

- **आरबीआइ भी चालू वित वर्ष के लिए जीडीपी अनुमान को ऊपर की ओर बढ़ा सकता है**
- **फिच ने कहा-2026-27 में विकास दर की इस तेजी को बनाए रखना मुश्किल होगा**

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: साख निर्धारित करने वाली एजेंसी फिच रेटिंग्स ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया। फिच ने कहा कि उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और जीएसटी सुधारों के साथ बेहतर धारणा के कारण वृद्धि अनुमान को बढ़ाया गया है। फिच की यह रिपोर्ट एक दिन बाद (पांच दिसंबर) को मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले आई है। बाजार और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि इस बैठक में आरबीआइ भी फिच की तरह चालू वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित कर सकता है। वर्तमान में आरबीआइ का अनुमान 6.5-6.7 प्रतिशत के दायरे में है, जिसे सात प्रतिशत से ऊपर ले जाया जा सकता है।

फिच की ग्लोबल इकोनमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ अप्रैल-जून की 7.8 प्रतिशत से भी तेज है और यह भारतीय इकोनमी में हो रहे लगातार सुधार को दर्शाता है। हालांकि एजेंसी का मानना है कि इस वित्त वर्ष के बाकी महीनों में विकास दर में कुछ नरमी आएगी, लेकिन पूरे साल का औसत 7.4 प्रतिशत रहेगा। हालांकि फिच का यह अनुमान है कि इसके बाद के वित्त वर्ष (2026-27) में इस विकास दर की तेजी को बनाए रखना मुश्किल होगा और भारत की विकास दर तब घटकर 6.4 प्रतिशत पर आ सकती है। फिच ने महंगाई की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आरबीआइ की तरफ से ब्याज दरों में एक और कटौती किए जाने की संभावना जताई है। भारत में अभी खुदरा महंगाई की दर रिकार्ड निचले स्तर 0.3 प्रतिशत पर है। फिच मानती है कि इससे दिसंबर में एक बार फिर रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश बनेगी। 2025 में अब तक रेपो रेट में 100 आधार अंक (एक प्रतिशत) की कटौती हो चुकी है और दिसंबर में इसे 5.25 प्रतिशत तक लाया जा सकता है।

अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से निजी निवेश में भी तेजी आने की उम्मीद

फिच का कहना है कि उपभोक्ताओं की तरफ से किया जाने वाला खर्च इस साल ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर बना हुआ है। अगले वित्त वर्ष के दूसरी छमाही से निजी निवेश में भी तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि वित्तीय स्थितियां और लचीली होंगी। हाल के दिनों में फिच के अलावा और भी कई एजेंसियों ने कहा है कि मौजूदा माहौल में आरबीआइ ब्याज दरों में एक और कटौती कर सकता है। हालांकि कुछ ऐसी एजेंसियां ऐसी भी हैं, जो यह मान रही है कि तेज आर्थिक विकास दर को देखते हुए आरबीआइ संभवतः इस बार ब्याज दरों को घटाने का फैसला नहीं करे। मौजूदा ब्याज दरों पर ही जब कर्ज की मांग तेज बनी हुई है।

2027 में जीडीपी सात प्रतिशत की दर से बढ़ेगी

नई दिल्ली, आइएएनएस: एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी के 2026 में 6.7 प्रतिशत, 2027 में सात प्रतिशत और 2028 में 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। वहीं वैश्विक विकास वृद्धि दर की बात करें तो यह 2026 और 2027 में 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। एसएंडपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कम महंगाई और मजबूत श्रम बाजार ज्यादातर विकासशील बाजार में कंज्यूमर खर्च को प्रोत्साहित करता रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे-जैसे अमेरिका और चीन में वृद्धि दर धीमी पड़ रही है, वैसे-वैसे उभरते बाजार अपनी मजबूती का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। यूरोजोन में भी रिकवरी जारी है। रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि उभरते बाजार 2026 में वैश्विक विकास का मुख्य इंजन होंगे और वैश्विक विकास दर में लगभग दो-तिहाई का योगदान देंगे।

S&P Global Ratings

बिहार में 35 वर्षों के बाद होगा मिट्टी का सर्वे

विश्व मृदा दिवस पर विशेष

ललन तिवारी ● जागरण

- पूरे प्रदेश के मिट्टी की जांच कर बनाया जाएगा हाईटेक डिजिटल प्रोफाइल
- भागलपुर-बांका से होगी शुरुआत, 1990 के बाद होगा प्रदेश में सबसे बड़ा सर्वे

भागलपुर : किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल लहलहा सकती है, यह पहले से ही तय करने के लिए बिहार में 35 वर्षों बाद इसकी वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इससे पहले 1990 में सर्वे किया गया था। प्रदेश के सभी 38 जिले की मिट्टी अब विज्ञान की कसौटी पर जांची-परखी जाएगी।

मिट्टी की जांच कर हाईटेक डिजिटल प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। सर्वे के बाद यह जानकारी मिल जाएगी कि राज्य के किस भू भाग में कहां कौन-सी फसल बेहतर पैदावार देगी। यह मैपिंग न केवल बिहार में कृषि अनुसंधान का फलक बढ़ाने में कारगर होगी, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगी। सर्वे के पहले चरण की शुरूआत भागलपुर व बांका से होगी। हर जिलों से संकलित किए गए डेटा से किसानों को बेहतर खेती करने का मार्गदर्शन मिलेगा। सर्वे कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए 56 तकनीशियनों की भी भर्ती की जाएगी। केंद्र सरकार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर को पूरे राज्य की हाईटेक मिट्टी मैपिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। इस प्रोजेक्ट से बिहार की मिट्टी की पूरी वैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार होगी, जिससे बेहतर बीज, फसल चयन और उर्वरता बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। यह योजना राज्य में रोजगार, आधुनिक तकनीक और कृषि अनुसंधान को नई ऊंचाई प्रदान करेगा।

बीएयू बनेगा देश का प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र

प्रोजेक्ट के लिए बीएयू में नई हाईटेक लैब स्थापित की जाएगी। जीआइएस और मैपिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा तथा आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। मिट्टी मैपिंग से किसानों को अपने गांव की मिट्टी कैसी है, इसकी स्पष्ट जानकारी मिलेगी। किस इलाके में कौन-सी फसल की खेती करना फायदेमंद होगा, किस क्षेत्र की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम या ज्यादा है, कहां बाढ़-सुखाड़ का असर ज्यादा है और किस जमीन की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किए जाने की जरूरत है आदि जानकारी मिल जाएगी।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर्मचारियों की जिम्मेदारी

राज्यों से कहा कि दबाव कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर करें विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एसआइआर के काम में लगे बूथ लेबल आफिसर (बीएलओ) पर अत्यधिक दबाव और दिक्कतों की दलीलों पर कहा कि राज्यों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग को जो कर्मचारी दिए हैं, कर्तव्यों का निर्वहन करना उन कर्मचारियों का दायित्व है। अगर बीएलओ पर काम का अत्यधिक दबाव है, तो राज्य सरकारें और कर्मचारी बढ़ाने पर विचार करें। अगर किसी बीएलओ के साथ कोई दिक्कत है, तो ऐसे मामलों में केस दर केस विचार किया जा सकता है।

ये टिप्पणियां और निर्देश प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जोयमाल्या बागची की पीठ ने बीएलओ पर काम के अत्यधिक दबाव और कई बीएलओ द्वारा आत्महत्या कर लेने का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने बीएलओ पर अत्यधिक दबाव की समस्या के निराकरण के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने ये आदेश तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद दिए। हालांकि, कोर्ट ने मरने वाले बीएलओ के लिए मुआवजा की मांग पर कोई आदेश नहीं दिया और कहा कि इस मुद्दे को पीड़ित परिवार या याचिकाकर्ता बाद में अर्जी देकर उठा सकता है। इससे पहले अर्जीकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने बीएलओ पर अत्यधिक दबाव और उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज किए जाने का मुद्दा उठाया। कहा कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर रहा है। इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई कहां तक सही है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा कि बीएलओ पर जो दबाव है, वह चिंता का विषय है। आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की है। उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। शिक्षक और आंगनबाड़ी कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। पीठ ने इन दलीलों पर कहा कि अगर राज्य सरकारों के सामने किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो उन्हें कोर्ट आना चाहिए। राज्य सरकार क्यों नहीं बता रही। अगर बीएलओ पर काम का इतना दबाव है, तो राज्य सरकारों को कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। नारायणन ने बीएलओ द्वारा काम के दबाव में आत्महत्या किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मामले के मानवीय पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकतीं। अगर कोई दिक्कत है तो उन्हें केस दर केस उस पर विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा एफआइआर दर्ज करने की बात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह ने कहा कि तमिलनाडु में 90 प्रतिशत गणना फार्म बांटे जा चुके हैं।

खरी-खरी

- जिन बीएलओ को कोई दिक्कत है, उनके मामलों पर केस दर केस विचार किया जाए
- कोर्ट ने ये आदेश अभिनेता विजय की पार्टी की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद दिए

एसिड हमले के मुकदमे में 16 साल की देरी न्याय व्यवस्था का मजाक : कोर्ट

जाब्यू, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमले के मुकदमे में 16 साल की देरी पर चिंता और नाराजगी जताते हुए गुरुवार को कड़ी टिप्पणियां कीं। शीर्ष अदालत ने मुकदमे के ट्रायल में अनुचित देरी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह न्याय व्यवस्था का मजाक है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली की रोहिणी अदालत में 2009 से लंबित मुकदमे को शर्म का विषय बताते हुए कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी इसे नहीं संभाल सकती तो कौन संभालेगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जोयमाल्या बागची की पीठ ने एसिड अटैक के मुकदमों की गंभीरता से लेते हुए देशभर के उच्च न्यायालयों से उनके यहां लंबित ऐसे मुकदमों का चार सप्ताह में ब्योरा मांगा है।

गांधी मैदान में आज से पुस्तकों का मेला, छात्रों का प्रवेश मुफ्त

जासं, पटना : राजधानी के गांधी मैदान में शुक्रवार से पुस्तकों की दुनिया सजेगी। सेंटर फार रीडरशीप डेवलपमेंट (सीआरडी) की ओर से आयोजित पुस्तक मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। मेले के संयोजक अमित झा ने बताया कि पांच से 16 दिसंबर तक चलने वाले पुस्तक मेले में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम पाठकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। मेले को लेकर तीन गेट बनाए गए हैं। जिन पर टिकट काउंटर मौजूद रहेंगे। यूनिफार्म में आने वाले स्कूल और कालेज के बच्चों का प्रवेश मुफ्त में होगा। सोमवार से शुक्रवार तक कालेज छात्रों को मुफ्त में टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। पुस्तक

गांधी मैदान में लगे पटना पुस्तक मेले में सजने लगे किताबों के स्टाल ● जागरण

मेले के अध्यक्ष व लेखक रत्नेश्वर ने कहा कि पुस्तक मेला कथाकार अवधेश प्रीत और शायर कासिम खुर्शीद को समर्पित होगा। मेला परिसर का द्वार और भवन ऋषियों और आचार्यों के नाम पर हैं। तीन मुख्य द्वार अगस्त्य, विश्वामित्र और चरक द्वार बनाए गए हैं। इसके साथ ही धन्वंतरि प्रशासनिक भवन, व्यास मंच, कश्यप मंच, माधव कला दीर्घा, भृगु हाल और आचार्य सुश्रुत थिएटर आकर्षण का केंद्र होगा।

मेले में तीन सौ से अधिक कार्यक्रम आयोजित होंगे

पुस्तक मेले के दौरान तीन सौ से अधिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें तेरी मेरी प्रेम कहानी, मुशायरा, कवि सम्मेलन, ज्ञान और गुरुकुल, संपादक से संवाद, युवा स्वर, किताब के शब्द उच्चरित हुए, जन संवाद, स्कूल उत्सव, हमारे हीरो आदि हैं। मेले का थीम वेलनेस अवे आफ लाइफ पर आधारित है। स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में जाने माने चिकित्सक से मानिसक और शारीरिक स्वास्थ्य पर संवाद करेंगे। मेले में राष्ट्रीय मुशायरा भी आयोजित होगा।

फिल्म अभिनेताओं से रूबरू होने का मिलेगा अवसर

पुस्तक मेले में पाठकों को फिल्म अभिनेताओं से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। सिनेमा-उनेमा कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन लघु और डाक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। त्रिपाठी की लाली और अखिलेंद्र मिश्र की बारात आकर्षण का केंद्र होगा। सिने संवाद में त्रिपुरारी शरण, फिल्म समीक्षक अनंत विजय, एएन पांडेय, विनोद अनुपम आदि विशेषज्ञों को सुनने का अवसर मिलेगा। सिनेमा में योगदान देने वाले भोजपुरी अभिनेता कुणाल सिंह, प्रेमलता मिश्र, जयमंगल देव को सम्मानित किया जाएगा। देश के प्रमुख प्रकाशक मेले में आएंगे।

आज से खाते में आने लगेगी खेल सम्मान राशि

जासं, पटना : बिहार राज्य खेल सम्मान समारोह में चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को आज से 15 दिसंबर तक खेल सम्मान पुरस्कार राशि खाते में आने लगेगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने बताया कि पांच अक्टूबर को राजगीर में खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें 813 खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया था। 87 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र

बिहार राज्य खेल सम्मान समारोह में चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिलेगा लाभ, 813 खिलाड़ी पुरस्कृत किए गए

सौंपा गया था। शंकरण ने कहा कि इस वर्ष के खेल सम्मान समारोह में जितने भी खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया है उनकी राशि चुनाव के कारण खाते में नहीं जा पाई थी। नई सरकार बनने के साथ अब खिलाड़ियों के खाते में राशि प्रदान की जाएगी। अगर किसी खिलाड़ियों को 15 दिसंबर तक राशि नहीं आयी तो वह खेल प्राधिकरण में आकर संपर्क कर सकते हैं। वहीं डोपिंग में संदिग्ध पाए गए कोच रमेश नागापुरी को सम्मान नहीं दिया जाएगा। महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने बताया कि उनकी राशि और सम्मान रोक दिया गया है।

मेडल लाओ, नौकरी पाओ के तहत बिहार के 87 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई। इसमें 39 महिला और 48 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। खेल सम्मान राशि पाने वाले 813 लोगों में 152 पैरा खिलाड़ी, 631 खिलाड़ी, 23 प्रशिक्षक, 5 खेल संघ और एक खेल अधिकारी शामिल थे। इस तरह कुल 783 खिलाड़ियों, जिनमें 297 महिला और 486 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे, को सम्मानित किया गया था। 2022 से इस वर्ष 2025 तक बिहार के 2085 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बीच 23.5 करोड़ की खेल सम्मान राशि सरकार ने वितरित किया है।